भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1537

गुरूवार, 12 फरवरी, 2026/23 माघ, 1947 (शक)

ग्रामीण क्षेत्रों मे नौकरियाँ

1537. श्रीमती जेबी माथेर हीशम:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत ग्यारह वर्षो के रुझानों सहित देश में वर्ष 2014 की तुलना में लिंग-वार बेरोजगारी दर कितनी हैं;

(ख) 15-29 आयु वर्ग के युवाओं और शिक्षित युवाओं के लिए अलग-अलग लिंग-वार बेरोजगारी के आंकड़े क्या हैं;

(ग) निरक्षर व्यक्तियों और स्नातक डिग्रीधारियों के लिए तुलनात्मक आंकडों सहित 30-59 आयु वर्ग के वयस्कों से संबंधित बेरोजगारी के लिंग-वार आंकड़े क्या हैं;

(घ) विगत पाँच वर्षो के दौरान गांवों सहित ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित नौकरियों के राज्य/संघराज्य क्षेत्र-वार आंकड़े क्या हैं; और

(ङ) कृषि, वस्त्र, आवास, स्वास्थ्य देखरेख और शिक्षा में 'जहाँ घर, वहीं नौकरी' दृष्टिकोण के अंतर्गत स्थानीय रोजगार सृजन के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ): रोजगार और बेरोजगारी का डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से एकत्र किया जाता है जिसे वर्ष 2017-18 से सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा करवाया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 6.0% से घटकर वर्ष 2023-24 में 3.2% हो गई है और इसी अवधि के दौरान पुरुषों के लिए 6.1% से घटकर 3.2% और महिलाओं के लिए 5.6% से घटकर 3.2% हो गई है।

पीएलएफएस से पहले, श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 2010-11 से 2016-17 के लिए रोजगार-बेरोजगारी सर्वेक्षण (ईयूएस) आयोजित किया गया था। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पंचवर्षीय रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण भी करवाता था। ऐसा पिछला सर्वेक्षण 2011-12 के दौरान किया गया था। इन सर्वेक्षणों जैसे पीएलएफएस, ईयूएस और पंचवर्षीय रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण के परिणाम अलग-अलग नमूना पद्धति और कवरेज के कारण तुलनीय नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त, वर्ष 2017-18 और वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तरों के 15-29 वर्ष की आयु के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

बेरोजगारी दर (% में)				
सामान्य शैक्षिक स्तर	2017-18		2023-24	
	पुरूष	**महिला**	**पुरूष**	**महिला**
साक्षर और प्राथमिक शिक्षा तक	9.8	2.1	3.4	1.0
पूर्व-माध्यमिक	14.7	8.3	5.0	2.2
माध्यमिक	14.7	12.8	5.4	3.5
उच्चतर माध्यमिक	20.3	24.7	9.3	7.6
माध्यमिक और उससे अधिक	23.5	32.5	13.8	19.2

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

साथ ही, 15-59 वर्ष की आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) देश में 2017-18 में 6.5% से घटकर 2023-24 में 3.5% और इसी अवधि के दौरान पुरुषों के लिए 6.6% से 3.5% और महिलाओं के लिए 6.0% से 3.4% हो गई है। इसके अलावा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित यूआर निरक्षरों के लिए 2017-18 में 1.2% से घटकर 2023-24 में 0.2% और इसी अवधि के दौरान स्नातकों के लिए 17.2% से 13.0% हो गई है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2019-20 में 53.3%, 2020-21 में 55.5%, 2021-22 में 55.6%, 2022-23 में 59.4% और 2023-24 में 62.1% है। पीएलएफएस रिपोर्ट में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, लिंगवार, शिक्षा-वार विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट https://www.mospi.gov.in/publications-reports पर देखा जा सकता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना

(सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण प्रदान करके कौशल भारत मिशन (एसआईएम) का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अलावा, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

*****